# अगले तीन साल में निर्यात सवा लाख से 3 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे : नंद गोपाल नंदी

योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा निर्यातकों व उद्यमियों की सुविधा के लिए निर्यात ऐप बनेगा। यूपी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि अगले तीन साल में निर्यात का सवा लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये करेंगे। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बन रही है। हर जिले में निर्यात केंद्र खोलेंगे। साथ ही नई चुनौतियों के मद्देनजर मौजूदा निर्यात नीति में भी बड़ा बदलाव होगा। वहीं नोएडा में इलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
मंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। निर्यातकों व उद्यमियों की सुविधा के लिए निर्यात ऐप बनेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना पोर्टल बनेगा। अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन भी शुरू होगा।

**नोएडा बनेगा गेटवे ऑफ यूपी**

नंद गोपाल नंदी ने नोएडा की संभावनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि वह नोएडा को गेटवे ऑफ यूपी की तर्ज पर विकसित कराएंगे। उसे इस तरह शोकेस किया जाएगा जो भी राज्य में आएगा वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यहां नए तरीके से हरियाली विकसित होगी। बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। नोएडा के लिए आगामी 50 सालों का विजन डाक्यूमेंट बनेगा।

**नोएडा व ग्रेटर नोएडा पर जारी होगा श्वेत पत्र**

नोएडा/ग्रेटर नोएडाØ में चल रही सभी परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र जारी होगा। इसमें आवंटियों, उनकी सम्पत्तियों की स्थिति, 2007 से अब तक न्यायालय में लंबित मामले, एनसीएलटी के विवाद आदि के समाधान का ब्यौरा होगा। बहुत अच्छा परफामेंस करने वाली इकाईयों की सूची बनेगी। पूरे एनसीआर में आईटी, मनोरंजन, उद्योग,कारोबार , ई-कॉमर्स सहित सभी सर्विस इंडस्ट्रीज की एक विधिवत कार्ययोजना बनेगी।

**आवंटियों का समाधान कराएंगे**

मंत्री ने कहा कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के पास बकाया पैसा वापस लाया जाएगा। बिल्डर, डेवलपर के लिए समाधान योजना लाई जाएगी ताकि एक लाख लोगों के घर फ्लैट उन्हें दिलाए जा सकें।

**हर जिले से चिन्हित होंगे एनआरआई**

हर मण्डल में निवेश के लिए शहरी विकास का एक माडल बनेगा। हर जनपद के एनआरआई को चिन्हित कर उसके द्वारा अपने जनपद/मण्डल के लिए उसकी विशेषता व राय के अनुसार क्या-क्या हो सकता है-इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनेगी। एक ऐप/ पोर्टल के अलावा इन्वेस्टमेंट एनआरआई बोर्ड बनेगा।